रेलवे की सौर ऊर्जा निविदा को नहीं मिले बोलीदाता, बोली की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

रेलवे की जमीन पर एक हजार मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए जारी निविदा पर सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ताओं की प्रतिक्रिया फीकी है। सूत्रों ने बताया कि सरकारी एजंसी एसईसीआइ के पास पहले ही 14 गीगावाट (14,000 मेगावाट) अधिशेष क्षमता की परियोजनाए उपलब्ध है।

अग्रणी सौर ऊर्जा कंपनियों के तीन सूत्रों ने कहा कि भारतीय रेलवे (49 प्रतिशत) और राइट्स लिमिटेड (51 प्रतिशत) की संयुक्त उद्याम कंपनी रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आरईएमसीएल) की निविदा पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिसके कारण बोली की समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है। सौर परियोजनाओं की बोली लगाने वाली सरकारी एजंसी भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआइ) के पास पहले ही मांग से अधिक 14 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता की परियोजनाएं उपलब्ध है, जो परिचालन और कार्यान्वय के विभिन्न चरणों में है। एसईसीआइ पहले ही प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए बिजली काफी सस्ती दरें हासिल कर चुकी है। उनकी राय में ऐसे में रेलवे को नई क्षमता जोड़ने के लिए एक और केंद्रीय एजंसी से निविदाएं मंगवाने से अच्छा होगा कि वह इन परियोजनाओं से बिजली ले। सूत्रों ने कहा कि किसी भी विकासकर्ता ने अब तक निविदा के लिए बोली नहीं लगाई है।

प्रस्तावित खनन सुधार एक माह में

दो-तीन साल में 500 खंड की नीलामी करेगी सरकार : जोशी

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार की योजना एक महीने में प्रस्तावित खनन सुधार लाने की है। कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संशोधनों के बाद खनिज खंड की नीलामी दो से तीन माह में शुरू होगी। खान मंत्रालय ने इससे पहले आम लोगों, खनन उद्योग और अन्य अंशधारकों से खान व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित सुधारों पर सुझाव मांगे थे।

जोशी ने साक्षात्कार में कहा, 'हम इन सुधारों को जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। एक माह या उससे आगे प्रस्तावित खनन सुधार लाए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि सरकार को प्रस्तावित सुधारों पर जो सुझाव मिले हैं, उन पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना अगले दो से तीन साल में कम से कम 500 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की है।

प्रस्तावित सुधारों के तहत एमएमडीआर कानून के 10ए(2)(बी) और 10ए(2)(सी) प्रावधानों में सुधार शामिल है। इससे पुराने समय से अटके 500 संभावित पट्टों (लीज) की नीलामी का रास्ता खुल सकेगा। धारा 10ए(2)(बी) शुरुआती या संभाव्य लाइसेंसों से संबंधित है। वहीं 10ए(2)(सी) खनन पट्टा देने से संबंधित है। धारा 10ए(2)(बी) और 10ए(2)(सी) को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन वह इसके ब्योरे में नहीं जाना चाहेंगे। खान मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज ब्लॉकों की नीलामी से पहले राज्य सरकारों को भरोसे में लेना होगा।

खान मंत्रालय सिर्फ नीति बनाता है, नीलामी से संबंधित अन्य कामकाज राज्य सरकारों को देखना होता है। सरकार ने मई में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधार लाने की घोषणा की थी।

संभवतः उम्मीद से अधिक तेजी से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था : रपट

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

भारतीय अर्थव्यवस्था संभवतः उम्मीद से अधिक तेजी से उबर रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में नरमी के रुख को अब छोड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर पूर्वानुमान लगाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स की रपट में यह अनुमान लगाया गया है।

रपट में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन छह फीसद से अधिक रहेगी और केंद्रीय बैंक दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखेगा। रपट कहती है, 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्तूबर में कोविड-19 से पूर्व के उच्चस्तर पर पहुंच गई है। ईंधन को छोड़कर अन्य श्रेणियों में दाम बढ़े हैं। चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति अपने अधिकतम स्तर पर होगी और 2021 में हमें इस पर अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।'अंडों और सब्जियों के दाम चढ़ने से अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति करीब साढ़े छह साल के उच्चस्तर 7.61 फीसद पर पहुंच गई है। यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से कहीं अधिक है।

बीपीसीएल निजीकरण : सोमवार को बंद होगी बोली, सभी निगाहें रिलायंस पर

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के लिए प्रारंभिक बोलियां सोमवार को बंद हो जाएंगी। ऐसे संकेत हैं कि ब्रिटेन की बीपी, फ्रांस की टोटल और सऊदी अरामको जैसी बड़ी कंपनियों के बोली लगाने की संभावना नहीं लगती है।

सरकार भारत में दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और विपणन कंपनी बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 फीसद हिस्सेदारी बेच रही है और वह चार मौकों पर शुरुआती अभिरुचि पत्र (ईओआई) दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ा चुकी है। मौजूदा समयसीमा 16 नवंबर है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) सचिव तुहिन कांता पाण्डेय ने पिछले महीने पीटीआई-भाषा को बताया था कि समयसीमा को अब और नहीं बढ़ाया जाएगा।

उद्योग सूत्रों ने कहा कि बीपी और टोटल के बोली लगाने की संभावना नहीं है। ऐसी खबरें भी हैं कि रूस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी रोजनेफ्ट या उसकी सहयोगी और सऊदी अरब की तेल कंपनी (सऊदी अरामको) कीमत को देखते हुए बोली लगाने की बहुत इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया परंपरागत ईंधन से हट रही है, 10 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब की कीमत काफी अधिक है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने पारंपरिक ईंधनों की मांग को घटाया है और हाइड्रोजन व बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल उम्मीद से अधिक तेजी से बढ़ सकता है।

बीएसई पर शुक्रवार को 412.70 रुपए के बंद भाव पर बीपीसीएल में सरकार की 52.98 फीसद हिस्सेदारी 47,430 करोड़ रुपए की है। साथ ही अधिग्रहणकर्ता को जनता से 26 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश करनी होगी, जिसकी लागत 23,276 करोड़ रुपए होगी। सूत्रों ने कहा कि बीपीसीएल सालाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाती है और इस गति से निवेशक को बोली की 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूलने में आठ से नौ साल लगेंगे। यह अधिग्रहण उन कंपनियों के लिए अधिक लाभदायक लगता है, जो कारोबार के साथ ही परिचालन क्षमता और मौजूदा कारोबार के साथ तालमेल के जरिए लाभ को बढ़ा सकती हैं।

अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) ऐसी एक कंपनी हो सकती है। आरआइएल गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन परिसर का संचालन करती है और खुदरा कारोबार में विस्तार का इरादा रखती है। रिलायंस ने अभी तक बीपीसीएल को लेकर अपने इरादों पर चुप्पी बनाए रखी है।

रिलायंस ने हाल में बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष सार्थक बेहुरिया को नियुक्त किया था और कुछ हफ्ते पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह को भी नियुक्त किया। सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों को बीपीसीएल के लिए बोली लगाने की इच्छा से जोड़ा जा सकता है।

सूत्रों ने कहा कि यह फैसला तार्किक लगता है क्योंकि रिलायंस अपनी जामनगर रिफाइनरी को बीपीसीएल की मुंबई, कोच्चि और बीना इकाइयों के साथ संयोजित कर सकती है और अपने 1406 से अधिक ईंधन स्टेशनों का बीपीसीएल के 17,138 पेट्रोल पंपों के साथ विलय कर सकती है।

यह तर्क रोजनेफ्ट के नेतृत्व वाली नायरा एनर्जी पर भी लागू होता है, जो गुजरात के वडिनार में दो करोड़ टन की तेल रिफाइनरी का संचालन करती है और उसके 5,822 पेट्रोल पंप भी हैं। हालांकि, ऐसे संकेत हैं कि रोजनेफ्ट बीपीसीएल के लिए बोली लगाने की इच्छुक नहीं है।

जमाखोरी रोकने के लिए जूट नियामक चलाएगा तलाशी अभियान

कोलकाता, 15 नवंबर (भाषा)।

जूट की जमाखोरी रोकने के लिए इस उद्योग के नियामक ने तलाशी और जब्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। एक अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

नियामक ने आदेश दिया था कि कच्चे जूट का 17 नवंबर से 500 क्विंटल से अधिक भंडारण नहीं किया जा सकता है। नियामक ने यह आदेश जूट की जमाखोरी रोकने के लिए दिया था। अब तलाशी और जब्ती की योजना इसी आदेश पर सख्ती से अमल कराने के लिए तैयार की गई है।

जूट आयुक्त के कार्यालय ने इससे पहले अगस्त में भंडारण की सीमा 1,500 क्विंटल निर्धारित की थी। बाद में छह नवंबर के आदेश में सीमा को घटाकर 500 क्विंटल कर दिया गया। आयुक्त कार्यालय ने छह नवंबर को जारी आदेश में भंडारण करने वालों को 10 दिन में भंडार कम करने के लिए कहा था।

यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब कच्चे जूट का भाव छह हजार रुपए प्रति क्विंटल से भी ऊपर निकल गया है। इससे जूट के बोरे बनाने वालों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जूट आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारी योजना भंडारण सीमा को उचित तरीके से अमल में लाने के लिए निहितस्वार्थ वाली शक्तियों का इस्तेमाल कर तलाशी व जब्ती अभियान चलाने की है। हम इसके लिए तैयार रहेंगे और किसी भी समय इसके संबंध में कदम उठा सकते हैं क्योंकि भंडारण संबंधी नया आदेश 17 नवंबर से अमल में आने वाला है।'

प्राप्त खुफिया जानकारियों के आधार पर नियामक का मानना है कि कच्चे जूट के भाव में अचानक आई तेजी का कारण बिचौलियों के द्वारा जमाखोरी किया जाना है। किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

जुट आयुक्त कार्यालय का कहना है कि कच्चे जूट की कीमत 5,600 से 5,700 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस बीच जूट बेलर एसोसिएशन ने भंडारण की नई सीमा लागू किये जाने के विरोध में 23 नवंबर से सारी व्यापारिक गतिविधियां स्थगित करने की घोषणा की है।

अप्रैल-अक्तूबर में सोने का आयात 47 फीसद घटकर 9.28 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

चालू वित्त वर्ष के पहले सात माह अप्रैल-अक्तूबर के दौरान सोने का आयात 47.42 फीसद घटकर 9.28 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

सोने का आयात चालू खाते के घाटे (कैड) को प्रभावित करता है। कोविड-19 महामारी की वजह से सोने की मांग बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे पीली धातु के आयात में भी भारी गिरावट आई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में सोने का आयात 17.64 अरब डॉलर रहा था। हालांकि, अक्तूबर में सोने का आयात 36 फीसद बढ़ा है। अप्रैल-अक्तूबर के दौरान चांदी का आयात भी 64.65 फीसद घटकर 74.2 करोड़ डॉलर रह गया।

सोने और चांदी के आयात में गिरावट से देश के व्यापार घाटे में भी कमी आई है। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार घाटा होता है। अप्रैल-अक्तूबर में व्यापार घाटा घटकर 32.16 अरब डॉलर रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 100.67 अरब डॉलर था।

भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है। मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए सोने का आयात किया जाता है। भारत सालाना 800 से 900 टन सोने का आयात करता है। चालू वित्त वर्ष के पहले सात माह में रत्न व आभूषणों का निर्यात 49.5 फीसद घटकर 11.61 अरब डॉलर रह गया।

'एनपीएस के तहत नियोक्ताओं के योगदान को सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त किया जाए'

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अगले बजट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत नियोक्ताओं के 14 फीसद के योगदान को सभी श्रेणियों के अंशधारकों के लिए करमुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने का फैसला किया है। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने यह जानकारी दी।

एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन में नियोक्ताओं के 14 फीसद के योगदान को एक अप्रैल, 2019 से करमुक्त किया गया है। बंद्योपाध्याय ने कहा, 'हम संभवतः नियोक्ताओं के 14 फीसद के योगदान को सभी के लिए करमुक्त करने का प्रस्ताव करने जा रहे हैं। अभी यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है।'

पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा, 'ऐसे में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसे सभी कर्मचारियों को दिया जाए। चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो या किसी कॉरपोरेट इकाई का कर्मचारी। सभी क्षेत्रों के अंशधारकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य मांग कर रहे हैं कि 14 फीसद का कर लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई राज्य सरकारों ने इस बारे में पीएफआरडीए को पत्र लिखा है।

इसके अलावा पीएफआरडीए सरकार से टियर-दो एनपीएस खाते को करमुक्त करने का लाभ सभी अंशधारकों को देने का आग्रह करेगा। बंद्योपाध्याय ने कहा, 'टियर-दो एनपीएस खातों को हाल में विशिष्ट रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए करमुक्त किया गया है। ऐसे में इसमें भी हम सरकार को सभी अंशधारकों को लाभ देने का आग्रह करेंगे। करमुक्त टियर-दो खाते में लॉक-इन की अवधि तीन साल की होती है, क्योंकि इसे करमुक्त का दर्जा मिला है। हम चाहते हैं कि इसका विस्तार अन्य सभी कर्मचारियों तक किया जाए।'

रिलायंस की खुदरा इकाई ने अर्बन लैडर की 96 फीसद हिस्सेदारी 182 करोड़ में खरीदी

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई ने ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैडर की 96 फीसद हिस्सेदारी का 182.12 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार देर रात शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी।

उद्योग जगत ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा बदलने, सीमा दो एमबीपीएस तक बढ़ाने की मांग की

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

उद्योग संगठन बीआइएफ ने देश में ब्रॉडबैंड की परिभाषा बदलने की मांग की है। अब समय आ गया है कि इसकी परिभाषा बदलें और स्पीड की सीमा को मौजूदा 512 केबीपीएस से बढ़ाकर दो एमबीपीएस किया जाए।

ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआइएफ) ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संचार की प्रौद्योगिकी तेजी से बदली है। देश में डाटा सेवाओं का पूरी तरह से नया बाजार सामने आया है। अभी कई सारे ऐसे आधुनिक इंटरनेट उपकरण हैं और ऐसी जरूरतें हैं, जिनके लिए मौजूदा सीमा से अधिक स्पीड की जरूरत होती है।

बीआइएफ ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कहा, 'हमारा यह मानना है कि ब्रॉडबैंड की मौजूदा परिभाषा न तो प्रौद्योगिकी के विकास के और न ही अधिक स्पीड वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं की भारतीय उपभोक्ताओं की चाह के अनुकूल है। अतः ऐसे में निश्चित ही इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और इसे बदला जाना चाहिए।' बीआइएफ ने नियामक के परामर्श पत्र 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और विस्तृत ब्रॉडबैंड स्पीड की रूपरेखा' को लेकर यह सुझाव दिया है।

ट्राई ने 'क्या ब्रॉडबैंड की मौजूदा परिभाषा की समीक्षा किए जाने की जरूरत है' और 'क्या डाउनलोड व अपलोड स्पीड की सीमा को बदला जाना चाहिए' समेत विभिन्न मुद्दों पर संबंधित पक्षों की राय जानने के लिए यह परामर्श पत्र जारी किया था। बीआइएफ के अध्यक्ष टीवी रामाचंद्रन ने इस बारे में संपर्क किये जाने पर कहा कि 512 केबीपीएस स्पीड की मौजूदा परिभाषा काफी कम है। इसे बढ़ाकर दो एमबीपीएस किया जाना चाहिए।

बीआइएफ का कहना है कि 4जी आ जाने के बाद भी भारत में ब्रॉडबैंड स्पीड वैश्विक मानकों की तुलना में आधी है। संगठन ने कहा कि कम से कम दो एमबीपीएस की डाउनलोड व अपलोड स्पीड वाली इंटरनेट सेवाओं को ही ब्रॉडबैंड कहा जाना चाहिए।

अमेरिका में स्थानीय लोगों की भर्ती बढ़ा कर वीजा पर निर्भरता कम की इन्फोसिस ने

नई दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा)।

सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनी इन्फोसिस अमेरिका जैसे बाजारों में वहीं के लोगों को काम पर रख कर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इससे कंपनी 63 फीसद कर्मचारियों के मामले में वीजा की आवश्यकता से छुटकारा पा चुकी है।

यूरोप, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बाजारों में भी कंपनी को आधे से अधिक कर्मचारियों के लिए वीजा लेन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंफोसिस अमेरिका को अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक मानती है।

इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राव ने विश्लेषकों की हाल ही में हुई बैठक में कहा, 'हम प्रतिभाओं को लाने-ले जाने में चुनौती देख रहे हैं। अमेरिका में नए प्रस्तावित आव्रजन नियमों से मजदूरी की लागत, वीजा देने, वीजा की वैधता अवधि और अनुपालन की समग्र लागत पर प्रभाव पड़ सकता है। हमने तीन साल पहले स्थानीयकरण कार्यक्रम को शुरू किया था। अमेरिका, यूरोप और आस्ट्रेलिया में इस कार्यक्रम की मदद से नए प्रस्तावित आव्रजन नियमों के प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक दूर करने में हमें मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ में इन्फोसिस के पास आठ नवोन्मेष केंद्र, नौ वैश्विक डिजिटल स्टूडियो (मेलबोर्न में एक 5जी स्टूडियो समेत) और सात वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र हैं।

STANDARD SURFACTANTS LIMITED
Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762
E-mail: headoffice@standardsurfactants.com, Website: www.standardsurfactants.com
Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950

EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR QUARTER ENDED ON 30.09.2020
(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	2309.29	2165.43
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	89.58	23.69
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	89.58	23.69
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	62.95	37.93
5.	Total comprehensive Income for the period	62.95	37.93
6.	Paid up Equity Share Capital	711.26	711.26
7.	Earning per share (Face value of Rs. 10/- each):		
	1. Basic	0.89	0.53
	2. Diluted	0.89	0.53

Notes:
1. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 13, 2020. The statutory auditors have carried out limited review of these financial results.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results are available on stock exchange websites and on Company's website.

For Standard Surfactants Limited
Pawan Kumar Garg
Chairman & Managing Director
DIN-00250836

Place: Kanpur
Date: 13.11.2020

ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN NO. U27310WB1920GOI003601
''कांकरिया सेंटर'', (4था एवं 5वाँ तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोल-71

निविदा आमन्त्रण सूचना (एनआईटी)

''अच्युतापुरम, आन्ध्र प्रदेश में ग्रास रूट ऑयल टर्मिनल के लिए भूमि के विकास, आरसीसी रिटैनिंग वाल्स, कम्पाउण्ड वाल, बिल्डिंग्स (नियंत्रण कक्ष, पीएमसीसी, सिक्युरिटी रूम, वाटर हाउस), फ्लेक्सिवल तथा रिजिड पेवमेन्ट्स कल्वर्तस'' के सिलसिले में निम्न कार्यों के निष्पादन के लिए दो भाग बोली प्रणाली में ऑन लाइन ''एकल प्रतिशत दर'' बोली/ प्रस्ताव आमंत्रित है।

क्रम सं.	कार्य का नाम	एनआईटी सं. एवं होस्टिंग की तिथि	प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि
1.	उप-अनुबंध आधार पर उसके स्वयं की सामग्रियों, मशीनरी तथा मानव-शक्ति के साथ साधारण सिविल एवं सड़क कार्यों जैसे पीसीसी, आरसीसी. फार्मवर्क, री इन्फोर्समेन्ट एवं ईंजर्ट्स, ब्रिकवर्क, प्लास्टरिंग, पेवर ब्लॉक तथा कंक्रीट रोड कार्यों का निष्पादन।	बी एंड आर/ एचओ/ 51205/ टीडी/ जनरल सिविल एवं सड़क कार्य/ 01 तिथिः 16.11.2020	30.11.2020 को 4.00 बजे अप. के भीतर

इच्छुक बोलीदाताओं को सरकार की ई-प्रापण प्रणाली में अपना सूचीकरण एवं पंजीकरण कराना होगा तथा https://eprocure.gov.in/eprocure.app पर लॉगिंग कर निविदा दस्तावेज डाउनलोड करना होगा। शुद्धिपत्र/ संवर्धन, यदि कोई हो, सीपीपी पोर्टल अर्थात् https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर तथा कम्पनी की वेबसाईट https://www.bridgeroof.co.in पर ही प्रकाशित होगी।

AMIN TANNERY LIMITED
CIN No.U19115UP2013PLC055834
Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P)
Ph. No.: +91 512 2304077, Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020 (₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Three Months ended 30.09.2020 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2020 (Unaudited)
1.	Total Income	623.86	874.79	867.81
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	89.29	76.07	89.95
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	6.54	8.27	(67.07)
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	6.54	8.27	(67.07)
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1.68	5.97	(53.27)
6.	Total Comprehensive Income for the period.	0.64	(1.40)	0.44
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹ 1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹1/-each) (Not Annualized *)			
i	Before Extraordinary Items (in ₹)	0.01	0.01	(0.05)
ii	After Extraordinary Items ((in ₹)	0.01	0.01	(0.05)

Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year ended financial results are available on the Stock Exchange websites:-www.bseindia.com and on the Company's website www.amintannery.in
2 . Key Standalone Financial Information:

Sl. No.	Particulars	Three Months ended 30.09.2020 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2020 (Unaudited)
1.	Total Income	623.86	874.79	867.81
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	89.29	76.07	89.95
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	6.54	8.27	(67.07)
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1.68	5.97	(53.27)

3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries [together referred as the "Group"] have been prepared in accordance with Ind AS 110 – Consolidated financial statements"
4. The Group has adopted IND AS 116 - Leases, effective April 1,2019 as notified by The Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules 2019, using modified retrospective method. The adoption of this standard does not have any material impact on the consolidated profit and earnings per share for the periods.

For and on behalf of the Board of Directors
Veqarul Amin
Managing Director
DIN No.: 00037469

Place: KANPUR
Date: 13.11.2020